LOK SABHA

Wednesday, March 22, 1978/Chitra 1, 1900 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*].

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Production of consumer goods by Foreign Multinational Companies

*407. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to lay a statement showing:

(a) whether Government are contemplating action against those foreign multinational companies as are producing non-priority consumer goods items like soap, footwear, matches, chocolate, toothpaste, biscuits etc. in the same way as was done in the case of Coca Cola;

(b) what are the names and country of origin of foreign multinationals producing consumer goods in India and what are their total market shares in India both in terms of rupee sales and quantum of production; and

(c) whether Government are considering any plan under which foreign multinationals as well as large Indian Industries are forced to vacate production in consumer goods over a ten-year phased programme so that production can be transferred to the decentralised sector?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Foreign companies producing low priority consumer goods are required to dilute their foreign holding to 40 per cent as per provisions of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973. So long as they comply with the directive issued under FERA, they can continue their operations and the question of taking any action against them would not arise. The case of Coca Cola company is somewhat different. They were also permitted to operate in India with non-resident interest not exceeding 40 per cent in accordance with the provisions of the said Act. The decision to close down their activities was taken by the company itself as a matter of their corporate policy and not as a result of any directive from the Government.

(b) According to the information available with the Department of Company Affairs the names and country of origin of foreign companies producing consumer goods like soap, footwear, matches, chocolate, toothpaste and biscuits in India are given below:—

Name of the company & Industrial activity	Name and country of holding/parent company
1	2
SOAP	
1. Hindustan Lever Ltd.	Uni Lever Ltd., U.K.
FOOTWEAR	
1. Bata India Ltd.	Leader A.G. St. Moritz, Switzerland.

1	2
MATCHES	
1. WIMCO Ltd.	Swedish Match Company, Sweden.
CHOCOLATE	
1. Cadbury Fry India Pvt. Ltd.	Cadbury Schweppes Overseas Ltd., U.K.
TOOTHPASTE	
1. Beecham (India) Pvt. Ltd.	Beecham Group Ltd., U.K.
2. Hindustan Lever Ltd.	Uni Lever Ltd., U.K.
3. Colgate Palmolive (India) Pvt. Ltd.	Colgate Palmolive Company, U.S.A.
4. Ciba Geigy of India Ltd.	Ciba Geigy Ltd., Switzerland.
BISCUITS	
1. Britania Biscuit Company Ltd.	Associated Biscuits International Ltd., U. K.

The detailed information regarding their total market shares in India both in terms of rupee sales and quantum of production is not centrally maintained in the Ministry of Industry.

(c) Government's policy towards foreign companies as well as large industrial houses has been set out in the Statement of Industrial Policy laid before the House on the 23rd December, 1977. No time bound plan has yet been drawn up for forcing such companies to phase out production in consumer goods.

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो मल्टी नेशनल्स हैं जो कंज्यूमर आइटम्स काटेज इंडस्ट्रीज़ और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ में बन सकती हैं, उनमें डील करते हैं, उनको यहां पर कंज्यूमर आइटम्स से धीरे-धीरे समाप्त करने की क्या योजना है और कितने वर्षों में यह इस में से समाप्त कर दिये जायेंगे ? अगर इनको इन आइटम्स में से हटा दिया जाये तो कितने लाख लोगों को यहां पर काम मिल सकता है ?

श्री जार्ज फर्नांडिस : अभी तक इस मामले में कोई भी समयबद्ध योजना नहीं बनाई गई है। जो औद्योगिक नीति सरकार की ओर से 23 दिसम्बर, 1977 को पेश की गई थी, उसमें यह था कि इसके आगे इस क्षेत्र में इनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ने देंगे और जो काम कुटीर उद्योग या लघु उद्योग में होना संभव है, उनको इस क्षेत्र में इनके आगे रखा जायेगा, कैपेसिटी वही दी जायेगी । मगर जिन आइटम्स में ये विदेशी कंपनियां हैं, इनके साथ बातचीत कर रहे हैं और वह इस दृष्टि से कर रहे हैं कि वे आहिस्ते-आहिस्ते इन क्षेत्रों से अपने आपको हटाती जायें । अगर इन क्षेत्रों में रहना हो तो उन क्षेत्रों में जायें जहां कंज्यूमर्स आइटम्स से निकलकर हाई टैक्नोलाजी या कैपिटल इंटेंसिव, जिसकी जरूरत है, और जिनको वह बना सकते हैं, उन क्षेत्रों में चले जायें । मगर कोई समयबद्ध कार्यक्रम इस पर नहीं बना है ।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : मंत्री महोदय का यह वक्तव्य समाचारपत्रों में आया है कि विदेशी कम्पनियों को कहा गया है कि जिन कंज्यूमर गुडज़ को स्माल स्केल सेक्टर बना सकता है, उसमें से वे अपने आप को हटा लें । मैं इस वक्तव्य को वैलकम करता हूं । मंत्री महोदय ने यह बहुत अच्छी बात कही है । लेकिन जनता पार्टी ने अपने इकानोमिक प्रोग्राम में लिखा है कि मल्टीनेशनल्ज को दस साल में बहुत से कंज्यूमर आइटम्ज में से जाना पड़ेगा । क्या मिनिस्टर साहब यह एशोर करेंगे कि जनता पार्टी के इकानोमिक प्रोग्राम में यह जो बात कही गई है, उसे इम्प्लीमेंट किया जायेगा ?

जहां तक मल्टीनेशनल्ज के ब्रांड नेम्ज का प्रश्न है, यह पालिसी बनी हुई है कि ब्रांड नेम्ज को धीरे धीरे खत्म कर दिया जायेगा, और आगे उन्हें यूज नहीं करने दिया जायेगा, ताकि हिन्दुस्तान में काटेज इंडस्ट्रीज का विकास हो सके । क्या मिनिस्टर साहब काटेज इंडस्ट्रीज को यह स्टचुटरी प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार हैं कि उन के द्वारा जो चीजें बनाई जायेंगी, बड़ी इंडस्ट्रीज उन्हें नहीं बना सकेंगी ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : माननीय सदस्य ग़लत हिन्दी बोल रहे हैं। वह अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल कर रहेहैं ।

श्री जार्ज फर्नांनडिस : जहां तक जनता पार्टी के दस बरस के कार्यक्रम का सवाल है, मुझे विश्वास है कि हम निश्चित तौर पर उसे पूरा कर पायेंगे । जहां तक ब्रांड नेम्ज का सवाल है, इस पर इस समय विचार चल रहा है और बहुत जल्दी ही इस बारे में निर्णय लिया जायेगा । जहां तक छोटे क्षेत्र की कंज्यूमर इंडस्ट्रीज को स्टैचुटरी प्रोटेक्शन देने का सवाल है, वह स्टैचुटरी प्रोटेक्शन देने की बात इस समय इस लिए पैदा नहीं होती है कि हम ने यह फ़ैसला लिया है कि हम बड़ी और विदेशी कम्पनियों को छोटे क्षेत्र में पैदा की जाने वाली चीजों के बारे में आगे अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की इजाजत नहीं देने वाले हैं । यह बात तय हो चुकी है । उन की कैपेसिटी बढ़ाने का सवाल नहीं है, फ़ेज आउट करने का सवाल है । उस पर हम बातचीत कर रहे हैं । लेकिन अभी तक हम ने इस बारे में कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं बनाया है ।

SHRI C. N. VISVANATHAN: Mr. Speaker, Sir, I want to refer to Wimco match industry. The Minister has said that he is going to reserve the match industry for the cottage sector. According to the Wimco authorities they are employing nearly one thousand persons. I would like to know if the Government is going to purchase the market shares of the Wimco factory and run it on cooperative basis the Government will take care of the interests of the present employees working over there.

SHRI GEORGE FERNANDES: One of the problem while we discuss the phasing out question is the problem of the existing employees and, as such, this question needs to be discussed. Sir, since match industry has been specifically mentioned, I may say that I have been discussing the match industry in public. Seventy per cent of the matches produced in India are produced in the cottage, household and small scale sector. Thirty per cent of the matches are produced by one multi-national, viz., WIMCO which has three factories in the country, that is, one in Madras, one near Bombay and one in Uttar Pradesh. WIMCO employs about 15,000 persons. I am aware of the fact if WIMCO were asked to give up their match producing activity and move to some other sector, to produce matches we will be able to give employment to about 2½ lakh people against 15,000 who are producing matches in the WIMCO factory. But there is this problem of the 15,000 persons who are working in the WIMCO factory. Therefore, I said phasing out takes time. These matters need to be discussed in detail so that no hardship may be caused to anyone.

श्री कल्याण जैन : जनता पार्टी की नीति के अनुसार कंज्यूमर गुड्ज को स्मालस्केल इण्डस्ट्रीज और कुटीर उद्योगों में बनाया जायेगा । मंत्री महोदय को जानकारी होगी कि साबुन उद्योग को स्मालस्केल सैक्टर में घोषित नहीं किया गया है । क्या मंत्री महोदय कम से कम वनस्पति घी का निर्माण करने वाले कारखानों को यह कह देंगे कि वे साबुन उद्योग बन्द कर दें ? क्या इस के लिए मंत्री महोदय तैयार हैं ?

दूसरी बात---जो छोटे कारखाने वाले सामान बनाते हैं उस के लिए उन को मार्केट मिल सके इसका कोई ऐसा उपाय क्या मंत्री महोदय और सरकार के विचाराधीन है कि इन की एक्साइज़ बढ़ाई जाय ताकि छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग वालों को प्रोटेक्शन मिल सके ?

श्री जार्ज फर्नांनडिस : जहां तक साबुन का सवाल है वाशिंग सोप तो स्माल स्केल सेक्टर के लिए रिज़र्व किया गया है, टायलेट सोप अभी उस तरह से रिजर्व नहीं किया गया है । जैसा कि मैंने कहा इस सवाल पर कोई एक फ़रमान निकाल कर तत्काल उस को अमल में लाने की स्थिति में हम नहीं हैं। क्योंकि कई समस्याएं इस में जुड़ी हुई हैं । इस पर विचार हो रहा है और मुझे विश्वास है कि हम कोई रास्ता इस में निकाल सकेंगे ।

वनस्पति घी की भी बात तो वही है कि हिन्दुस्तान लिवर इस क्षेत्र में काफी बड़ी मात्रा में काम कर रहा है और काफी देश के भीतर दूसरी बड़ी कम्पनियां हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं । मुझे यह बात स्वीकार है कि इस को हम छोटे क्षेत्र में कर सकते हैं । लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये फ़ेज आउट करने की बातें हैं । सब सम्बन्धित लोगों से बातचीत करके हमें इस में से रास्ता निकालना पड़ेगा ।

जहां तक एक्साइज़ प्रोटेक्शन देने का सवाल है सिर्फ़ एक्साइज़ से ही यह काम नहीं होने वाला है । छोटे उद्योगों की कई समस्याएं हैं, मार्केटिंग की, पैसे की और मैनेजमेंट इत्यादि की समस्याएं उन की हैं। इस के अलावा किस क्षेत्र में लगाया जाय, कौन चलाने वाले हैं, किस तरह से उस का सारा व्यवहार है, यह सारी समस्याएं हैं। यह जो नीति हम चला रहे हैं उस नीति से हमें विश्वास है कि उन की सारी समस्याओं को हम हल कर पाएंगे और एक्साइज़ में किसी विशेष छूट की आवश्यकता हो तो वह भी देने में कोई अड़चन नहीं है । वह सवाल सामने आने पर उस को भी देख लेंगे ।

श्री लालू प्रसाद : क्या यह सच है कि उद्योग मंत्री ने शार्पेज लिमिटेड को उपभोक्ता वस्तु जैसे ब्लेड पर विदेशी नाम ईरासमीक लिखने की अनुमति दे दी है जब कि सरकार की नीति है कि उपभोक्ता वस्तुओं पर कोई भी विदेशी कम्पनी ऐसा नहीं करेगी ? यदि ऐसा होगा तो अन्य विदेशी कम्पनियां भी क्या इस का इस्तेमाल नहीं करेंगी ?

श्री जार्ज फर्नांनडिस : इस के लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: I want to know whether the Government is prepared to sell the shares of the WIMCO to its employees and Engineers.

SHRI GEORGE FERNANDES: Government dose not own the shares of the WIMCO. WIMCO is owned by the shareholders.

Import of Electric Generators for New Power Projects in Gujarat

*408. SHRI AHSAN JAFRI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether the electric generators produced by Bharat Heavy Electricals Ltd., are not so superior as compared to foreign units;

(b) whether the Central Government are of the opinon that for new power projects foreign units are to be imported; and

(c) whether Gujarat Government has asked permission of the Central Government for the import of foreign manufactured units for its new power projects?